(ख) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय सरकार के परिव्यय से, अपनी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के स्त्रोतों से, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है । इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं ।

(ग) गुजरात में इस विभाग की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्योरा विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(घ) वर्ष 1993 के दौरान खाली विडियो कैसेटों, श्याम तथा श्वेत और रंगीन टीवी, कॉम्पैक्ट डिस्क तथा कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइवों के विनिर्माण के लिए और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं के अंतर्गत सॉफ्टवेयर विकास के लिए गुजरात राज्य में स्थित इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए 3 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है । जिसमें 85 लाख अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश शामिल है ।

विवरण

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की चल रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

क्र. सं०	परियोजनाओं/कार्यक्रम
1	2
1.	मूल संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित
(क)	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
(ख)	इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केंद्र
2.	प्रायोजित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं
(क)	कम लागत के डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति (वीएचएफ) ओमनी रेंज (डीवीओआर) तथा परम्परागत वीओआर प्रणाली का विकास
3.	जनशक्ति विकास से संबंधित
(क)	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास परियोजना (जनशक्ति खण्ड)
(ख)	विज्ञान निष्णात, इलेक्ट्रॉनिकी के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम
(ग)	कम्प्यूटर के लिए विशिष्ट जनशक्ति का सृजन (अध्यापक प्रशिक्षण)
4.	सामाजिक विकास
(क)	विवेक दर्पण (श्रव्य-दृश्य मूल संरचनात्मक सुविधाएं)

Assistance for Technology Sought by Madhya Pradesh Government

3946. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Govern ment has urged the Central Government to provide necessary assistance for the setting up a centre for photonics technology for electronics design and technology and a software technology park in the State;

(b) if so, whether Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation has set up a state-of-the-art integrated facility for design, development and manufacture of fibre optic communication products;

(c) whether the Union Government have examined the proposal of Madhya Pradesh; and

(d) if so, by when a final decision in this regard is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDU-ARDO FALEIRO): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The proposal of the State Government of Madhya Pradesh seeking support for setting up a Centre for Electronics Design and Technology and Software Technology Park in the State has been examined. The Government of India will extend necessary technical and administrative support for establishing these facilities by the Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation (MPSEDC).

The proposal for setting up a Centre for photonics Technology has been reformulated jointly with MPSEDC and Optel Telecommunication Limited (OTL) as Optoelectronics Technology Project to be implemented by OTL, Bhopal on a cost sharing basis. This is being procewed farther.